Financial Assistance for Orissa and Rajasthan under Urban Employment and Poverty Eradication Schemes

*302. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) The amount of financial assistance released till date by Government to Orissa/Rajasthan Governments during the last two years and the amount to be released during the Ninth Five Year Plan period under Urban Employment and Poverty Eradication schemes, year-wise and State-wise;

(b) the number of beneficiaries from these programmes till date, State-wise;

(c) whether the amount provided by Government has properly been utilised, if not, whether any enquiry has so far been conducted; and

(d) if so, with what results?

THE MINISTER OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHRI SUKHDEV SINGH DHINDSA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) With the aim of eradicating urban poverty an unified programme called Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY) is being implemented by this Ministry with effect from 1.12.1997. The details of Central share released to Orissa and Rajasthan during the 9th Five Year Plan for the Programme are as follows:—

(Rupees in lakhs)

Name of State	1997-98 Released	1998-99 Released	1999- 2000 Tentative Allocation	Released
Orissa	223.11	360.44	403.63	82.72
Rajasthan	329.91	620.52	694.64	142.00

The allocation for the remaining two years of the 9th Five Year Plan will be based on the Demands for Grants for the respective years.

(b) The number of benificiaries assisted under various components of SJSRY, as per the latest quarterly progress report received from the State Governments of Orissa and Rajasthan, is as follows:—

Name of State	No. of benefinciaries assisted under USEP	No. of benefinciaries assisted under DWCUA	No. of mandays of work generated under UWEP (in lakhs)	No. of benefinciaries covered under Community Structure (in lakhs)
Orissa	4929	95	10.97	12,070
Rajasthan	9216	Nil	3.60	9.460

USEP = Urban Self Employment Programme
DWCUA = Development of Women and Children in Urban Areas
UWEP = Urban Wage Employment Programme

(c) As reported by the State Governments, the funds released are utilized for implementation of the Programme. In the absence of a specific complaint no inquiry has been conducted.

(d) Does not arise.

श्री राम दास अग्रवाल: सभापति महोदय, मैंने दो स्टेट्स उड़ीसा और राजस्थान के बारे में प्रश्न पूछा है और दुर्भाग्य से 1999 का वर्ष उड़ीसा के लिए और राजस्थान के लिए बहुत अधिक कठिनाई भरा वर्ष रहा है। उड़ीसा में सुपर साइकलोन आया, जिसकी वजह से वहां पर जो प्रकृति ने प्रकोप किया उससे सारी स्टेट के करीब 14 जिले प्रभावित हैं और जो उसका दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। उसी प्रकार से, सभापति जी, राजस्थान में दुर्भाग्य से इस बार ऐसा अकाल पड़ा है, जैसा पिछले कई वर्षों से नहीं पड़ा था। इसीलिए मैंने यह प्रश्न उठाया था कि केन्द्र की ओर से इन दोनों राज्यों में, जो इस समय सबसे अधिक पीड़ित और प्रभावित हैं और जहां की बहुत बड़ी जनसंख्या इस समय इन दोनों ही प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से आतंकित व परेशान हैं, वहां के लिए कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई है। हमारे मंत्री महोदय ने जो मेरे प्रश्न के संदर्भ में उत्तर दिया है, उसमें मैं केवल इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इस समय जो अकाल की स्थिति है उसके कारण वहां पर एंपलायमेंट का सवाल खड़ा है, वहां पर लोगों को सहायता देने का सवाल खड़ा है। यह बात ठीक है कि दोनों स्टेट्स इस समय आर्थिक संकट से भी गुजर रही हैं, उसके कारणों में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन दोनों स्टेट्स से इस समय एक तरह से उनके मुख्यमंत्री बोल चुके हैं कि उनके पास सहायता करने के लिए, उनके पास राहत के कार्य खोलने के लिए, उनके पास अकाल या बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए पैसा नहीं है। यह बात वह बार-बार कह चुके हैं, इसलिए इस समय हमारे सामने यह

सवाल खड़ा हो गया है कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से इस प्रकार की राहत दी जाए ताकि जो धन वह एंपलायमेंट के लिए या राहत के कार्यों के लिए चाहते हैं वह उनको तुरन्त रिलीज किया जाए।

सभापति जी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि इस समय जो एलोकेशन हुआ है अर्बन डवलपमेंट के लिए, अर्बन एंपलायमेंट के लिए, बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए उसमें से केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सरकार को 403 करोड़ रुपए इस साल 1999-2000 के लिए देने का तय किया था, लेकिन उड़ीसा सरकार से जो रिपोर्ट केन्द्र सरकार के पास आई है, उसके अनुसार 82.7 करोड़ रुपया विदड्रा किया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह केन्द्र सरकार के फंडस क्रंचेज की वजह से ऐसा हुआ है या राज्य सरकार ने इस प्रकार के और धन की मांग ही नहीं की है या उनके पास इस धन को खर्च करने का कोई प्लान नहीं है? सर, मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि राजस्थान के संबंध में भी यही स्थिति है, ऐलोकेशन किया गया है 694 करोड़ रुपए का, लेकिन अभी तक दिया गया है 142 करोड़ रुपया। मैं इन्हीं दोनों राज्यों के संदर्भ में मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने नहीं दिया या उन्होंने मांग नहीं की? अगर आपने नहीं दिया तो कब देंगे और अगर उन्होंने मांग नहीं की है तो आपको उसका कोई कारण अगर पता लगा हो तो कृपा करके वह बताएं?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: चेयरमैन सर, जहां तक बजट ऐलोकेशन का सवाल है, इस ऐलोकेशन के लिए प्लानिंग कमीशन ने एक ऐक्सपर्ट ग्रुप बनाया था जिसकी रिपोर्ट 1993-94 में आई और उसी हिसाब से टोटल बजट का 10 परसैंट ऐलोकेशन नार्थ-ईस्टर्न स्टेट्स को होता है, 90 परसैंट हर स्टेट की जो बिलों पावर्टी लाइन पापुलेशन है, उसके मुताबिक उनको ऐलोकेशन होता है। ऐसे ही राजस्थान और उड़ीसा का इसमें दिया है कि इतने रुपए का ऐलोकेशन इनको हुआ है। यह हम स्टेट गवर्नमेंट को 75:25 परसैंट पर देते हैं, जिसे स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है और इसका काफी हिस्सा, मोर देन दि 50 परसैंट, अनस्पेंट मनी के रूप में दोनों स्टेट्स के पास पड़ा है। अगर वे इसे खर्च कर लें तो हम दूसरा भी देने को तैयार हैं, उसका भी ऐलोकेशन हो सकता है। लेकिन इन दोनों स्टेट्स की रिपोर्ट नहीं आई है और बहुत सा उनके पास ऐसा पैसा है जो अभी उन्होंने खर्च नहीं किया है। इसलिए यह स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वह उस पैसे को खर्च करें, उसके बाद हम देखेंगे।

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना कंट्रिब्युशन इसके लिए उपलब्ध नहीं हुआ होगा, इसलिए केन्द्र ने नहीं दिया। मैं इस संबंध में अपने प्रश्न का पहला भाग निवेदन कर रहा हूं कि मंत्री महोदय क्या इस बात की जांच कराएंगे कि क्या राज्य सरकार के पास कोई रुपया पड़ा है क्योंकि मैंने कई बार दोनों स्टेट्स के मुख्य मंत्रियों के स्टेटमेंट अखबारों में पढ़े हैं, जिनमें वे बार-बार यह शिकायत करते हैं कि केन्द्र उनको मदद नहीं करता है, केन्द्र उनका शोषण कर रहा है, केन्द्र आर्थिक सहायता नहीं देता है।

तो यदि आपके पास रुपया है और आप देने को तैयार हैं लेकिन राज्य सरकार लेने की स्थिति में नहीं है, तो इसके बारे में आपको जानकारी करके बताना चाहिए कि इस साल जो रुपया अनस्पेंट रह जाएगा, अनयूज्ड रह जाएगा, वह रुपया क्या आप उनको अगले वर्ष देंगे या उनका यह रुपया यहीं लैप्स हो जाएगा? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

सभापति जी, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है कि जो विभीषिका और प्रकृति का तांडव नृत्य हमको वहां देखने को मिला, उस संदर्भ में केन्द्र सरकार ने मदद की है और उड़ीसा में बहुत मदद की है। लेकिन उड़ीसा में उसका यूज़ किस प्रकार हो रहा है, उसका यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा या अनयूटिलाइजेशन हो रहा है, इन तीनों के मामले में क्या केन्द्र सरकार उड़ीसा के बारे में भी और राजस्थान के बारे में भी कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करेगी कि जो धन आप अकाल राहत के लिए और बाढ़ पीड़ितों के लिए या सुपर साइक्लोन पीड़ितों के लिए देना चाहते है, इन राज्यों की मदद जो आप कर रहे हैं, उसकी जांच आप कर सकें? यह मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: जैसा मैंने सवाल के जवाब में कहा है, कोई शिकायत नहीं है, किसी स्टेट से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन अनस्पेंट मनी के कई कारण और भी हैं, जैसे बैंक अब पैसा नहीं देते हैं, रिज़र्व बैंक ने तो कहा है कि विदाउट गारंटी उनको लोन दो लेकिन मोस्ट आफ दी बैंक्स उनको विदाउट गारंटी लोन नहीं देते हैं, इसलिए उनकी बहुत ऐप्लीकेशन्स पेंडिंग पड़ी हैं। हमारे डिपार्टमेंट ने चार-पांच मीटिंग्स की हैं और मैंने खुद इन सारी स्कीम्स में थोड़ी-बहुत जो समस्याएं आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए एक कमेटी बनाई है जो यह देखेगी कि इसकी जो गाइडलाइंस हैं, उसका बेसिक डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है, उसे कैसे अच्छी तरह से यूज़ किया जा सकता है। वह कमेटी बनी है जो तीन महीने के अंदर-अंदर इसकी रिपोर्ट देगी और जो इसमें खामियां होंगी, वे दूर कर दी जाएंगी।

SHRI NARENDRA MOHAN: Mr. Chairman, Sir, unfortunately, as far as the poverty alleviation programmes are concerned, the Government of India is consistently following a very weak-kneed policy. And this policy in Rajasthan and Orissa has always been implemented in a slip-shod manner. Orissa and Rajasthan are the States which are extremely poor. Rajasthan is facing a famine like situation for a number of years. Even the Report on Poverty Alleviation in India published by the Lok Sabha Secretariat states so. As per this Report, we find that consistently in all the Five Years Plans, including the 8th Five Year Plan, there has always been a weak-kneed policy with respect to measures needed for strengthening the various poverty alleviation programmes. The reasons for the same

have also been enumerated here. What is the Government of India doing in this regard? The earlier Government has not been very careful about Orissa and Rajasthan. The present Government has to show some grace because Rajasthan and Orissa are definitely having a lot of problems. Sir, I would like to tell the Minister that Rajasthan needs immediate help. Is the Government willing to give some immediate help? The reply states that under the DWCU the number of beneficiaries in Rajasthan is nil. How come that?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा था कि इसका जो ऐलोकेशन है, वह तो एक्सपोर्ट ग्रुप की तरफ से जो रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर होता है। मैंने इसीलिए वह कमेटी बनाई है ताकि जिन स्टेट्स को ज्यादा जरूरत है और इमीडियेटली जरूरत है, उनके लिए हम कुछ फंड एलॉट कर सकें। अभी जो व्यवस्था है, उसमें हम ज्यादा जरूरत के लिए और इमीडियेट जरूरत के लिए फंड एलॉट नहीं कर सकते हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट 3 महीने में आ जाएगी। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमारे रूल्स में कोई ऐसी संभावना हुई कि हम ज्यादा जरूरत के लिए तुरंत सहायता दे सकें, तो हम अवश्य देंगे।

श्री ओंकार सिंह लखावत: सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है कि वह अपनी वार्षिक योजना में कटौती कर रही है। मैं अपने पूरक प्रश्न के भाग (क) में मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब राजस्थान सरकार अपनी वार्षिक योजना में कटौती कर लेगी तो केन्द्रीय सरकार की ओर से शहरी गरीबी उन्मूलन और शहरी विकास के नाते जो पैसा दिया जाएगा, क्या उसमें केन्द्रीय सरकार भी उस कटौती के अनुरूप कटौती करेगी? यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है।

श्री सभापति: काफी है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सभापति महोदय, जैसी मैंने स्कीम बताई है ऑनरेबल मेंबर साहब को, कि 75:25 रेशियो से हम ग्रांट देते हैं। अगर वे अपनी योजना में कटौती करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां से दी जाने वाली ग्रांट कम हो जाएगी क्योंकि अभी जो रूल है, उसके मुताबिक हम तो 75 प्रतिशत राशि देंगे।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, this is a Plan scheme. With the aim of providing assistance and support to the poor, a unified programme called Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana was started. But, what I heard is that a lot of things such as famine relief, natural calamity relief, etc., have been brought in. So far as this

scheme is concerned, it has nothing to do with the famine relief or drought relief or any other relief. There must be identified beneficiaries. Sir, the guidelines are there. Sir, I would like to know from the hon. Minister, while implementing the scheme from the year 1997-98, whether the Government has found or received any complaint from the State Governments in regard to the difficulties faced by them in the implementation of these programmes and policies due to these guidelines. I would also like to know whether the beneficiaries are not in a position to take advantage of this scheme because in a particular State, namely, Rajasthan, we find that the number of beneficiaries under DWCUA is nil. In this connection, I would like to know from the hon. Minister whether the Government have received any complaint from the State Governments or the beneficiaries with regard to the implementation of these guidelines relating to this scheme. Are there any changes being contemplated in order to amend the present guidelines?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: चेयरमैन सर, जैसा मैंने पहले बताया कि उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। मैंने अपनी तरफ से सब चीफ मिनिस्टर साहबान को चिट्ठी लिखी है कि इसमें क्या खामियां हैं, क्यों नहीं लागू हो रही है और इसके क्या कारण हैं? जनवरी में मैं सब सैक्रेटरीज और मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बुलाने जा रहा हूं। जहां-जहां यह कमियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई है वह भी उस पर विचार करेगी और जो इसमें खामियां रहेंगी उनको दूर करने की कोशिश करेगी।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Sir, the hon. Minister in his reply has stated that Rs. 403.63 crores and Rs. 694.64 crores have been released for Orissa and Rajasthan. I would like to know exactly on which date the amounts were released because, after its release, as you know, if the election process had started, the Code of Conduct would have come into force. It may also be one of the reasons for money not being spent.

Sir, part (b) of my supplementary is, in case of Orissa and Rajasthan, specially in case of Orissa, is it because of 'super cyclone' that the State Government was not able to contribute its share? And, I further want to know whether the Government of India will also

consider to waive out the State shares and show some special consideration in the case of Orissa?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर, इसमें सारा कुछ दिया है कि किस-किस फाइनेंशियल इयर में कितना एलोकेशन हुआ, कितना रिलीज हुआ और कितना अन-एक्सपेंडेड मनी है इसमें सब डिटेल्स दी हुई है। अगर यह डेट चाहेंगे तो मैं उनको भिजवा दूंगा अभी मेरे पास डेट नहीं है। दूसरा जो है, वह मैंने पहले ही बतला दिया है।

DR. M.N. DAS: Mr. Chairman, Sir, I am thankful to hon. Shri Ramdas Agarwal for raising this question. I am sure the hon. Minister knows it well that, after independence, two capital cities were built. The first one was Bhubaneshwar in Orissa and the second one was Chandigarh in Punjab. Over the last fifty years, both the cities have expanded beyond the expectation, population has multiplied, numerous structures have come up and they have almost become the pride of India for the beauty they present and also for the activities they have undertaken.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

DR. M.N. DAS: Sir, my question is, after the 'super cycline', today, the city of Bhubaneshwar has become a 'ghost city'. It is not only Bhubaneshwar, which has become a ghost city, but also Cuttack, a thousand-year-old city, which is also standing as a ghost city. One of the most holy and ancient cities of Orissa, Jajpur, stands devastated. Under these peculiar and painful circumstances, is the Government considering how to alleviate the poverty of the people in these devastated areas of Orissa in particular, and how to rehabilitate the poor, the slum-dwellers and the working-force in the cities of Bhubaneshwar, Cuttack and Jaipur?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर, जहां तक इस स्कीम की बात है वह तो मैंने पहले बता दिया। लेकिन उड़ीसा के लिए स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट ने और हुडको ने, 387.5 करोड़, जो बिलो पावर्टी लाईन हैं उनको और एल०आई०जी० हाउसेज के लिए लोन दिया है और स्टेट के जो 50,000 मुलाजिम हैं उनके लिए मकान बनाने के लिए भी हुडको कोशिश कर रही है और उनके लिए भी पैसा सैंक्शन किया गया है। लेकिन मूल सवाल से यह ताल्लुक नहीं रखता है। लेकिन फिर भी जितना हमारे से हो सकता है हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं।